(b) the number and names of persons to whom licences were given;

(c) the number and value of the bales of reptile leather said to have been seized at Bombay harbour in March, 1978; and

(d) the nature of disposal of the seized property?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) During last three years export of reptile skins except non-poisonous snake skins was banned. Non-poisonous snake skins were allowed for export on quota basis with a limited ceiling released for export from time to time which have also now been banned completely.

(b) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

तस्करी में गतिविधियों में सरकारी अधिकारियों का सम्बद्ध होना

2817. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्करी की गतिविधियों को रोकने में विभागीय सहयोग प्राप्त करने में सरकार को किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या तस्करी की गतिविधियों में कुछ सरकारी अधिकारी सम्बद्ध पाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) जी, नहीं ?

(ख) और (ग). सरकार को मिली रिपोर्टों से पता चला है कि अप्रैल, 1977 से जुलाई, 1978 तक की अवधि में पुलिस और सीमाशुल्क विभागों के 13 सरकारी कर्मचारी, बम्बई और मद्रास में तस्करी के मामलों में ग्रस्त पाये गये थे। इन कर्मचारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की गयी थी।

पावरलुम एसोसिएशन, पिलखुआ द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचन

2818. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरलूम एसोसियेशन, पिलखुआ द्वारा उत्पादनशुल्क के अपवंचन के मामले की जांच अभी तक अनिर्णीत है जबकि इस मामले में शुल्क अपवंचन प्रकाश में आ चुका है;

(ख) पूरी जांच के पश्चात् पिछले वर्षों में कितनी कर/शुल्क राशि का अपवंचन पाया गया है ; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है और की गई जांच का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी।

Export of Indian Woollen Garments to European Market

2819. **SHRI KACHARULAL HEMRAJ JAIN:**

SHRI RAM PRAKASH TRIPATHI:

Will the the Minister of COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether India's share in the export of woollen garments to the European market is negligible;

(b) whether Government have made an assessment of export possibilities of Indian woollen grements to the European market; and

(c) what measures Government propose to take to export large number of woollen pieces?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI ARIF BEG): (a) India's exports of woollen garments to the European market has not been substantial so far

(b) Such assessment of items including woollen garments has been done from time to time by organisations like the Wool and Woollens Export Promotion Council, the Federation of India Exporters' Organisations, the Trade Development Authority and the Indian Institute of Foreign Trade

(c) For boosting exports, of woollen goods, Government have taken a number of measures which include sending of sales-cum-study teams/trade delegations, participation in exhibitions/fairs and continuance of compensatory support to provide incentive for such exports.

राज्य सरकारों द्वारा धनराशि जमा कराने को बजाय सहकारी बैंकों को प्राथमिकता देना

2820. **श्री जगदीश प्रसाद माथुर**: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारें तथा स्थानीय निकाय अपनी बचत की राशि जमा करने के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकों और डाकघरों की अपेक्षा केवल सहकारी बैंकों को प्राथमिकता देते हैं, और

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंक जो केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करते हैं, इस सुविधा से वंचित रह जाते हैं जिससे उन्हें पूंजी जुटाने में कठिनाई हो रही है तथा इस प्रकार वे क्षेत्रीय माग को पूरा करने में असमर्थ है ?

वित्त मंत्री (श्री एच० एम पटेल): (क) ग्राहक के रूप में, राज्य सरकारें उन बैंकों को स्वेच्छा से चुनने के लिए स्वतंत्र है जिनके साथ उनके स्थानीय निकायों, सावधिक प्राधिकरणों तथा सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों का बैंकिंग कारोबार हो। कुछ राज्य सरकारों ने, अपने अधीन की कुछ विशेष वर्गीकृत संस्थाओं को, वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं जैसे सहकारी बैंक, पोस्ट आफिस आदि को अधिशेष निधि की व्यवस्था के बारे में प्राथमिकता देने की सलाह दी है।

(ख) जी, नहीं। बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋण साधन भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/कृषि पुनर्वित तथा विकास निगम आदि से पुनर्वित्त उपलब्ध कराने के अलावा मुख्यत जन साधारण द्वारा जमा राशियों से जुटाए जाते हैं।

चीन द्वारा भारतीय तम्बाकू का आयात

2821. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा**: क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन ने भारत से तम्बाकू खरीदने की इच्छा व्यक्त की है,

(ख) यदि हां, तो आगामी वित्तीय वर्ष में कितने मूल्य के तम्बाकू का निर्यात किया जाएगा, और

(ग) क्या सरकार का विचार तम्बाकू के निर्यात के बदले सिल्क आयात करने का है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?